फारस की खाड़ी पर नई समस्या

लेखक- रमिन जहानबेगलो (प्रोफेसर, जिंदल. ग्लोबल यूनिवर्सिटी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

11 मई, 2019

"परमाणु समझौते से आंशिक रूप से खुद को अलग करने का ईरान का फैसला जोखिम से भरा और अमेरिकी मंसूबों के अनुरूप साबित हो सकता है।"

ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को घोषणा की कि ईरान 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से खुद को आंशिक रूप से अलग करेगा। P5 + 1 समझौते के रूप में ज्ञात संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना (Joint Comprehensive Plan Of Action - JCPOA) के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को कम करने का ईरान का निर्णय, अमेरिका द्वारा ईरान के तेल निर्यात को शून्य करने के हालिया प्रयास की प्रतिक्रिया के रूप में प्रतीत होता है। अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया के रूप में, ईरान मांग कर रहा है कि सौदे के शेष हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात् यू.के., चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस, अगले 60 दिनों में ईरान के बैंकिंग और तेल क्षेत्रों पर प्रतिबंधों को कम कर दें। यदि सौदे के पाँचों समर्थनकर्त्ता ईरान के पक्ष में कार्य नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो तेहरान के अधिकारी यूरेनियम का और अधिक संवर्धन शुरू कर देंगे और अरक परमाणु सुविधा पर काम फिर से शुरू कर देंगे।

धैर्य की हानि

ईरान की योजनाएँ बहुत स्पष्ट हैं और इन्होंने एवं बहुपक्षीय वार्ताओं पर विराम लगा दिया है, जो ईरान पर थोपे गये अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर सख्त सीमाएं लगाती हैं। निस्संदेह, ईरान का निर्णय एक ऐसे सौदे के साथ धैर्य की हानि के रूप में आया है, जो बहुत कम प्रस्तावित आर्थिक लाभ प्रदान कर रहा है। लेकिन अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यों को फिर से शुरू करके, ईरान एक बड़ा जोखिम उठा सकता है, जो यूरोप के साथ अपने राजनयिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है और ट्रम्प प्रशासन के मंसूबों को पूरा कर सकता है, अर्थात् तेहरान के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही।

जिसके बाद, ईरान आर्थिक रूप से अलग-थलग हो सकता है, लेकिन ईरान के लिए थोड़ी राहत की बात रूस का वह संदेश है जिसमें उसने कहा है कि ईरान अकेला नहीं है। इसके अलावा, क्रेमलिन ने तेहरान का साथ देते हुए परमाणु समझौते से पीछे हटने का मुख्य कारण अमेरिका को बताया है। हालांकि, ईरान द्वारा सौदे की कुछ शर्तों से अलग होने के निर्णय का दोष अमेरिका पर डालने के पीछे क्रेमलिन की मंशा कुछ दीर्घकालिक हितों के बिना नहीं है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध निश्चित रूप से मास्को और तेहरान के बीच सहयोग के विकास में सहायक साबित होगा, साथ ही यह तुर्की जैसे देशों के लिए भी सहायक सिद्ध होगा जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए मायने रखते हैं।

प्रतिबंधों की नई श्रृंखला को लागू करने में ट्रम्प प्रशासन का लक्ष्य ईरान की प्रमुख धातु कंपनियों, जैसे-मोबार्के स्टील और नेशनल ईरानी कॉपर इंडस्ट्रीज कंपनी की कमाई को प्रभावित करना है। इसका ईरानी सरकार के राजस्व पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह ईरान की भारी ऋणी धातुओं और खनन कंपनियों की बैलेंस शीट को भी खराब कर देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इस स्थिति का अनुसरण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को बढ़ाएगा, विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा नियोजित ब्लू-कॉलर श्रमिकों के बीच, जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

अशांति का फैलना

इसमें कोई रहस्य नहीं है कि पिछले साल 2.5 मिलियन सरकारी कर्मचारियों को कीमतों में तेजी आने के बावजूद कोई बढ़ोत्तरी नहीं मिली थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान पर ट्रम्प प्रशासन की 'अधिकतम दबाव' की नीति का उद्देश्य धातु उद्योग में नियोजित श्रमिकों को हड़ताल के लिए मजबूर करके (1980 के दशक में पोलैंड के सालिडैरीटी, मजदूर संगठन की शैली में) ईरानी शहरों में सामाजिक अशांति को बढ़ाना है।

डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों के लिए, ईरान के साथ टकराव का उद्देश्य स्पष्ट रूप से ईरानी शासन को उस धन से वंचित करना है जिसका उपयोग वह पश्चिम एशिया के चारों ओर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए कर सकता है, साथ ही इसका उद्देश्य ईरानी नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर भी दबाव डालना है। ट्रम्प प्रशासन के दृष्टिकोण के अनुसार, ईरान में आर्थिक अस्वस्थता आज या कल विरोध प्रदर्शन को सुनिश्चित करेगी। लेकिन क्या इसका मतलब अयातुल्ला के शासन के अंत की शुरुआत से भी है?

चीजें जितनी दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं अधिक जटिल हैं। अगर हम पश्चिम एशिया की भूस्थैतिक स्थिति पर नजर डालें, तो जेसीपीओए का उल्लंघन करने की ईरान की धमकी एक बहुत ही चिंताजनक निर्णय है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के दृष्टिकोण से, मि. ट्रम्प का अमेरिका एक ऐसा देश है जो सभी को सिर्फ कष्ट देता है। ट्रम्प प्रशासन के लिए, अमेरिका तेहरान में इस्लामिक शासन को पश्चिम एशिया में अपना दुश्मन नंबर एक मानता है।

जॉन बोल्टन, जो श्री ट्रम्प के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि यू.एस. अमेरिकी सहयोगियों को बचाने के लिए अमेरिका एक विमान-वाहक स्ट्राइक समूह और हमलावरों को पश्चिम एशिया भेज रहा था और उनका उद्देश्य ईरानी शासन को डराने की एक अचूक कोशिश में निहित है। पिछले कुछ हफ्तों में, व्हाइट हाउस ने तेहरान और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) में अधिकारियों के खिलाफ दबाव और धमकियों के अपने अभियान को तेज कर दिया है। वाशिंगटन की नजर में, आतंकवादी समूहों के समर्थन, मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु-संबंधी तकनीकों की खोज के कारण ईरान एक आतंकी देश है।

लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान ने इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों को धन मुहैया कराना, मिसाइल परीक्षण करना और बशर अल-असद के सीरियाई शासन को समर्थन देना जारी रखा। इस प्रकार, जिस बिंदु पर यह मुद्दा खड़ा है, वहाँ वार्ता की दिशा में पहल करने की कल्पना बहुत मुश्किल है।, हालांकि, कुछ यूरोपीय देश ईरानी संकट के राजनयिक प्रबंधन के लिए वापसी को प्रोत्साहित करना जारी रख सकते हैं। नवंबर, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक अमेरिकी पक्ष से ईरानी शासन के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई की संभावना बहुत कम है। ईरान निश्चित रूप से अमेरिका पर या जिस क्षेत्र में अमेरिकी सेना मौजूद है, वहा वहाँ मिलिशिया प्रॉक्सी के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से बदला लेने के तरीकों की तलाश करेगा। उस स्थिति में, ईरान और यू.एस. के बीच सैन्य टकराव की संभावना भी बढ़ती दिखती है।

अंत में, अगर ईरान का नेतृत्व सफलतापूर्वक अमेरिकी 'अधिकतम दबाव' का विरोध करता है, तो उसे सैन्य पथ चुनने के अलावा भी कुछ और करना होगा। जो लोग ईरान के खिलाफ किसी एकतरफा अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हैं, वे केवल यह आशा कर सकते हैं कि अयातुल्ला और आईआरजीसी इस क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं और उसके सहयोगियों पर हिंसक रूप अपनाते हुए प्रतिक्रिया नहीं देंगे और यदि ऐसा होता है, तो ईरान, पश्चिम एशिया और वैश्विक बाजार के लिए कई मुश्किलें सामने आ जाएंगी।

अमेरिका-ईरान विवाद

चर्चा में क्यों?

- ईरान ने घोषणा की है कि उसके परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए किए गए समझौते से वह आंशिक रूप से हट रहा है।
- राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि यदि 60 दिनों में किसी नए समझौते पर सहमति नहीं बन जाती तो ईरान यूरेनियम का और अधिक संवर्धन शुरू कर देगा।
- यह कदम बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनावों के बीच उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

- अमरीका द्वारा वर्ष 2015 के समझौते से हटने की घोषणा को एक वर्ष हो गया है। ईरान ने पाँच अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- पर्यवेक्षकों का कहना है कि समझौते को यदि और शक्तिहीन किया जाता है तो उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।
- इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पिओ ने घोषणा की थी कि ट्रम्प प्रशासन ग्रीस, इटली, भारत, जापान, चीन, तुर्की और दक्षिण कोरिया सहित आठ देशों को दी गई सभी छूटों को समाप्त कर रहा है, ताकि उन्हें ईरानी तेल से दूर किया जा सके और ईरानी तेल निर्यात को शून्य किया जा सके।
- हालांकि, जब ट्रम्प प्रशासन ने नवंबर में तेहरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया था, तब अमेरिका ने इन देशों को ईरानी तेल आयात करने के लिए अस्थायी छूट दी थी।

अमेरिकी प्रतिबंध का प्रभाव

- ईरान के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल निर्यात है, जो प्रतिबंध की वजह से संकट में आ जाएगा।
- वर्ष 2018 में वैश्विक तेल उत्पादन में ईरान का हिस्सा 4% था। ईरान पर प्रतिबंधों के पश्चात् वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ने की संभावना है।
- आपूर्ति में व्यवधान की वजह से तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- दुनिया के तीन सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वे वैश्विक तेल बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- अमेरिका ने कहा है कि वह तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था या कंपनी पर वित्तीय अंकुश लगाएगा, जिसमें कंपनियों द्वारा स्विफ्ट बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध, उन कंपनियों की किसी भी अमेरिकी संपत्ति की जब्ती और डॉलर में लेन-देन जैसे प्रतिबंध शामिल हैं।

भारत पर प्रभाव

- रिफाइनरियों के लिये तेल की आपूर्ति: अमेरिका के इस निर्णय से भारत पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- अमेरिका ने हाल ही में भारत के एक अन्य शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता, वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इन परिस्थितियों में अमेरिका का हालिया निर्णय भारत के लिये मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
- आयात बिल में वृद्धि से रुपए पर दबाव पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महँगाई बढ़ेगी।

संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना' (JCPOA) या 'वियना समझौता'

- वर्ष 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिये ईरान तथा P5+1 देशों (अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और जर्मनी) के मध्य एक समझौता किया गया।
- समझौते के अनुसार ईरान अपने परमाणु संयंत्रों की नियमित जाँच के लिये राजी हुआ, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं चल रहा है।
- इसमें ईरान द्वारा परिष्कृत यूरेनियम भंडार को 96 प्रतिशत तक घटाना और अपने सभी संयंत्रों को अतंर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिये खोलना शामिल है।
- इस समझौते का मकसद था परमाणु कार्यक्रमों को रोकना। इन शर्तों के बदले में पश्चिमी देश ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुए थे।
- इस समझौते के अनुसार ईरान ने अपने करीब नौ टन अल्प संवर्द्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम तक करने की शर्त स्वीकार की थी।

भारत-ईरान संबंध

- दोनों देशों का सालाना द्विपक्षीय व्यापार करीब 2 हजार करोड़ डॉलर है।
- जहाँ ईरान भारत की ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से को पूरा करता है, वहाँ भारत द्वारा ईरान को दवा, भारी मशीनरी, कल-पुर्जे और अनाज का निर्यात किया जाता है।
- दोनों देश सामरिक तौर पर एक-दूसरे के पुराने सहयोगी हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मध्य-पूर्व में दोनों देशों के साझा सामरिक हित भी हैं।
- ईरान की राजधानी तेहरान में दूतावास के अलावा जाहिदाद और बंदरअब्बास शहर में भारत के वाणिज्य मिशन हैं।
- भारतीय कंपनियाँ ईरान में कारोबार की बड़ी संभावनाएँ देखती हैं। ईरान के तेल रिफाइनरी, दवा फर्टिलाइजर और निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियाँ पैसा लगा रही हैं।
- उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा भारत मशीनरी, ऑटो और खनन क्षेत्र में भी ईरान के साथ सहयोग कर सकता है।
- ईरान के रास्ते भारत मध्य एशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और अफगानिस्तान में आसानी से दाखिल हो सकेगा।
- भारत के सहयोग से चाबहार बंदरगाह का भी विकास किया गया है। इसके साथ ही भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपने उत्पाद भेजने का वैकल्पिक रास्ता मिल गया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. वर्ष 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए ईरान तथा P5+1 देशों के मध्य ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था।
2. परमाणु अप्रसार संधि 1968 से प्रभाव में आयी थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

2. "संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना (JCPOA) के सन्दर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?

(a) यह योजना वियना समझौते के नाम से भी जानी जाती है।
(b) इसमें ईरान द्वारा परिष्कृत यूरेनियम भंडार को 80% प्रतिशत तक घटाना और अपने सभी संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए खोलना शामिल है।
(c) यह योजना 2015 में अस्तित्व में आयी थी।
(d) इसके अनुसार ईरान ने अपने करीब 9 टन अल्प संवर्द्धित यूरेनियम भंडार को कम करके 300 किलोग्राम तक करने की शर्त स्वीकार की थी।

1. Consider the following statements:-

1. The historic nuclear treaty between Iran and P5+1 countries was done to monitor Iran's nuclear programmes.
2. Nuclear Proliferation Treaty came into effect in 1968.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

1. Which of the following is incorrect about the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ?

(a) This scheme is also known as Vienna Agreement.
(b) This included the reduction of Iran's refined uranium reserve by 80% and to open all its plants to international observers.
(c) This scheme came into exitstance in 2015.
(d) According to this agreement, Iran had accepted the condition of reducing its nearly 9 tonnes of under refined uranium reserve to 300kg.

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- 'पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम एशिया भारी तनाव के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में ईरान द्वारा 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से खुद को अलग करने की घोषणा से इस तनाव के और अधिक विकराल रूप लेने की संभावना बढ़ गई है।' टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

Q. In last few years West Asia is going through bad phase of tension. Due to the Iran's decision to separate itself from the historic treaty of 2015, the possibility of this tension taking more severe form has increased. Comment. (250 Words)

प्रश्न:- वर्तमान में चल रहे अमेरिका-ईरान परमाणु विवाद के चलते भारत के कूटनीतिक-आर्थिक हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. India's diplomatic and economic interests are to be severely affected due to the US- Iran nuclear tension. Discuss. (250 Words)

नोट : 10 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।